

20



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2005/फाल्गुन 12, 1926

No. 59]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2005/PHALGUNA 12, 1926

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2005

सं. नू-23013/10/04-एल. टब्लू. (.).— ठेका श्रम (नियंत्रण एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा भारतीय तेल निगम, बालासोर, उड़ीसा के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम प्रणाली के उत्पादन के प्रश्न पर विचार के लिए एक समिति का गठन करती है।

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नांकित होंगे :—

- (1) श्री जी. वी. आर. शर्मा,  
प्लॉट संख्या 604,  
आर. टी. ओ. कार्यालय के सामने,  
गिरिपेठ कार्यालय,  
नागपुर-440010

सदस्य

- (2) श्री जी. डी. गुलाब,  
निदेशक (कार्मिक)  
महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड,  
सम्बलपुर

सदस्य

- (3) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय),  
भुवनेश्वर

सदस्य-संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे :—

“भारतीय तेल निगम के बॉटलिंग प्लांट, बालासोर, उड़ीसा के प्रतिष्ठान में अस्वीकृत सिलिंडरों को हटाने, वाशिंग प्लांट में लगी मशीन को चलाने एवं बंद करने, कन्वेयर बेल्ट पर कार्य, सिलिंडरों का कैप हटाने, “ओ” रिंग की देखरेख, भार क्षमता (टेयरवेट) का उल्लेख करना, कैरोजल में सिलिंडर भरने, कैरोजल इकाई से सिलिंडर हटाने, कैप लगाने, कैप बांधने, कैप को पंच करने, एल्यूमिनियम कैपिंग और सीलिंग के द्वारा कैप फिक्स करने, वाटर सोप सॉल्यूशन को भरने और खाली करने, शिफ्टिंग, स्टैकिंग और डिस्टैकिंग, लिपिकीय प्रकृति का कार्य, अकुशल प्रकृति के कार्य एवं अन्य विविध कार्य जिसमें भारतीय तेल निगम के बॉटलिंग प्लांट बालासोर,

उड़ीसा की साफ-सफाई आदि शामिल हैं, के कार्य में ठेका श्रम पद्धति (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि उक्त प्रतिष्ठान के उक्त जॉब्स/कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को निषिद्ध किया जाये अथवा नहीं।

4. समिति का मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा। समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी।

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### (Central Advisory Contract Labour Board)

#### RESOLUTION

New Delhi, the 3rd March, 2005

No. U-23013/10/04-LW (.)—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constituted a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of the Indian Oil Corporation, Balasore, Orissa.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under :—

- |  |                 |
|--|-----------------|
| (1) Shri G.V.R. Sarma,<br>Plot No. 604,<br>Opp. R.T.O. Office Giripeth,<br>Nagpur-440010 | Member          |
| (2) Shri G.D. Gulab,<br>Director (Personnel)<br>Mahanadi Coalfield Limited,<br>Sambalpur | Member          |
| (3) The Regional Labour Commissioner (Central),<br>Bhubneshwar                           | Member-Convenor |

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows :—

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of shifting of rejected cylinders, switching on and off machines engaged in washing plant, operation conveyor belt, decapping of cylinders, visual checks of “O” ring, marking of tare weight, feeding of cylinder into carousal, removal of cylinder from carousal unit, cap stitching, cap tying, cap punching, cap fixing by aluminium capping and sealing, water soap solution filling and evacuation, shifting, stacking and destacking, clerical nature of job, unskilled type of jobs and other misc. jobs including sweeping of plant in the establishment of Indian Oil Corporation Bottling Plant, Balasore, Orissa and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970”.

4. The Headquarter of the Committee will be at Bhubneshwar. The Committee should submit its report at the earliest.

T. A. SRINIVASAN, Secy.